सामाजिक स्टार्टअप्स : उद्देश्य के साथ उद्यम

ज्योति एस. वर्मा

भारत में सामाजिक स्टार्टअप्स उद्यमिता के पारम्परिक ढाँचे को बदलते हुए उद्देश्य, समावेशन और टिकाऊ विकास के सिद्धांतों पर आधारित नया मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। डिजिटल समावेशन, कौशल विकास, जलवायु संरक्षण पहल और सामुदायिक आजीविका जैसे क्षेत्रों में इन स्टार्टअप्स ने नवाचार को सामाजिक प्रभाव से जोड़ा है, जिससे रोज़गार के अवसर, वित्तीय पहुँच और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार उन क्षेत्रों तक हो रहा है, जो लंबे समय से विकास से वंचित थे। तकनीक-आधारित समाधान, स्थानीय उद्यमिता और सामुदायिक भागीदारी को साथ लेकर ये स्टार्टअप्स विकास की प्रक्रिया को अधिक सहभागी, न्यायसंगत और टिकाऊ बना रहे हैं। इस तरह, 'विकसित भारत' के विज़न को वास्तविकता में बदलने में उनकी भूमिका निर्णायक होती जा रही है।

भारत के सोशल स्टार्टअप्स बड़े पैमाने पर स्थायी बदलाव ला रहे हैं। ऐसा ही एक जीवंत उदाहरण राजस्थान के रेगिस्तानी गाँव तिलोनिया में देखने को मिलता है। यहाँ एक ऐसा संस्थान है जो यह दर्शाता है कि जब उद्देश्य स्थिरता से जुड़ता है, तो एक मिशन-आधारित और उद्यम-प्रेरित सामाजिक स्टार्टअप क्या कर सकता है। 1972 में स्थापित बेयरफुट कॉलेज एक सरल लेकिन क्रांतिकारी विश्वास के साथ शुरू हुआ कि सबसे गरीब समुदायों में अपनी ज़िंदगी बदलने की क्षमता और धैर्य पहले से मौजूद होता है, बस अक्सर उनके पास आर्थिक व्यवस्था में भागीदारी के लिए मंच, कौशल और अवसरों की कमी होती है।

पिछले पाँच दशकों में यही विश्वास एक वैश्विक विकास मॉडल में बदल गया है, जिसने हजारों 'बेयरफुट सोलर इंजीनियर', 'बेयरफुट टीचर', 'बेयरफुट डॉक्टर', 'बेयरफुट डेंटिस्ट' और जल, पर्यावरण, आजीविका, संचार और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है।

लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं। ईमेल : jyotisverma2912@gmail.com

आज, एक करोड़ से अधिक जीवनों पर प्रभाव डालते हुए, 5,000 दूरदराज़ गाँवों तक पहुँच बनाते हुए और 96 देशों में कार्य करते हुए, बेयरफुट कॉलेज ने दुनिया को यह दिखाया है कि वास्तविक सामाजिक परिवर्तन तभी स्थायी होता है, जब समुदायों को टिकाऊ उद्यम और स्वामित्व के माध्यम से सशक्त किया जाए।

बंकर रॉय जैसे दूरदर्शी नेताओं द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन पिछले दशक में व्यापक रूप से फैला है और अब सामाजिक स्टार्टअप्स की नई पीढ़ी में नए स्वरूप में उभर रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण सिक्किम की राजधानी गंगटोक से सामने आता है। OurGuest Travels (www.ourguest.in), जिसे अप्रैल 2025 में स्टार्टअप महाकुंभ में D2C (डायरेक्ट-टू-कंज़्यूमर) पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पूर्वोत्तर भारत का पहला ऑनलाइन *ट्रैवल एग्रीगेटर* है। यह प्लेटफॉर्म सिक्किम, उत्तर बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में चयनित होमस्टे, फार्म स्टे, रिसॉर्ट और निर्देशित पर्यटन अनुभवों का विशेष संग्रह प्रदान करता है। 600 से अधिक होमस्टे, 50 से अधिक प्रशिक्षित स्थानीय गाइड और 6,000 से अधिक पर्यटकों को सेवा प्रदान करके यह मंच दिखाता है कि पर्यटन-आधारित स्टार्टअप किस प्रकार ग्रामीण आजीविका को मज़बूत कर सकते हैं, स्थानीय संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं, इको-टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकते हैं और व्यावसायिक रूप से भी सफल रह सकते हैं।

राष्ट्र निर्माण में एक नई ताकत

सोशल स्टार्टअप्स ने भारत के जीवंत स्टार्टअप परिदृश्य में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है और देश को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में योगदान दिया है। ये उद्यम व्यापार की कठोरता को गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु सहनशीलता, स्वच्छ ऊर्जा, कौशल विकास, पहुँच और लैंगिक समावेशन जैसी गहन सामाजिक चुनौतियों के समाधान के प्रति प्रतिबद्धता के साथ जोड़ते हैं।

उन संस्थापकों के नेतृत्व में, जो जटिल समस्याओं को हल करने में अवसर देखते हैं, सोशल स्टार्टअप्स सफलता को नए तरीके से परिभाषित करते हैं। वे केवल आय नहीं बल्कि स्पष्ट और मापने योग्य सामाजिक प्रभाव के आधार पर भी अपने परिणाम देखते हैं।

आज सोशल स्टार्टअप्स विविध क्षेत्रों में सक्रिय हैं, जैसे *एडटेक प्लेटफॉर्म्स* जो वंचित छात्रों की सेवा करते हैं, *हेल्थ-टेक* नवाचार जो अंतिम मील आबादी तक पहुँचते हैं, वित्तीय समावेशन मॉडल, सतत कृषि समाधान, विकलांगता केंद्रित तकनीक, ग्रामीण आजीविका उद्यम, जलवायु प्रौद्योगिकी नवाचार और *सर्कुलर इकोनॉमी वेंचर्स*। कई स्टार्टअप्स ने पैमाने और स्थिरता का प्रदर्शन किया है और यह साबित किया है कि मुनाफा और उद्देश्य विरोधी नहीं बल्कि विकास के पूरक चालक हैं। सामाजिक प्रभाव एस्केलेटरों ने Haqdarshak का समर्थन किया, जो नागरिकों को कल्याण लाभों तक पहुँचने में मदद करता है और अब तक 7.6 मिलियन से अधिक परिवारों और 1,12,000 से अधिक व्यवसायों तक पहुँच चुका है। *फ्रंटियर मार्केट्स*, जो ग्रामीण महिला उद्यमियों को अंतिम मील आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से सशक्त बनाता है। Trestle Labs जिसका कुल बिक्री मूल्य 12 बिलियन रुपये दर्ज किया गया है, की सहायक तकनीकें दृष्टिहीन लोगों के लिए विकसित की गई हैं। अब 600 से अधिक संस्थानों में इन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख IITs, IIMs और राज्य एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। पूरे भारत में हज़ारों समान उद्यम उन चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं, जिन्हें कभी अत्यधिक जटिल, जोखिमपूर्ण या बाज़ार-आधारित दृष्टिकोण से असंभव माना जाता था।

सोशल उद्यमियों की बदलती प्रोफ़ाइल भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। अब संस्थापक केवल IIT और IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से नहीं आते, बल्कि वे सीधे उन समुदायों

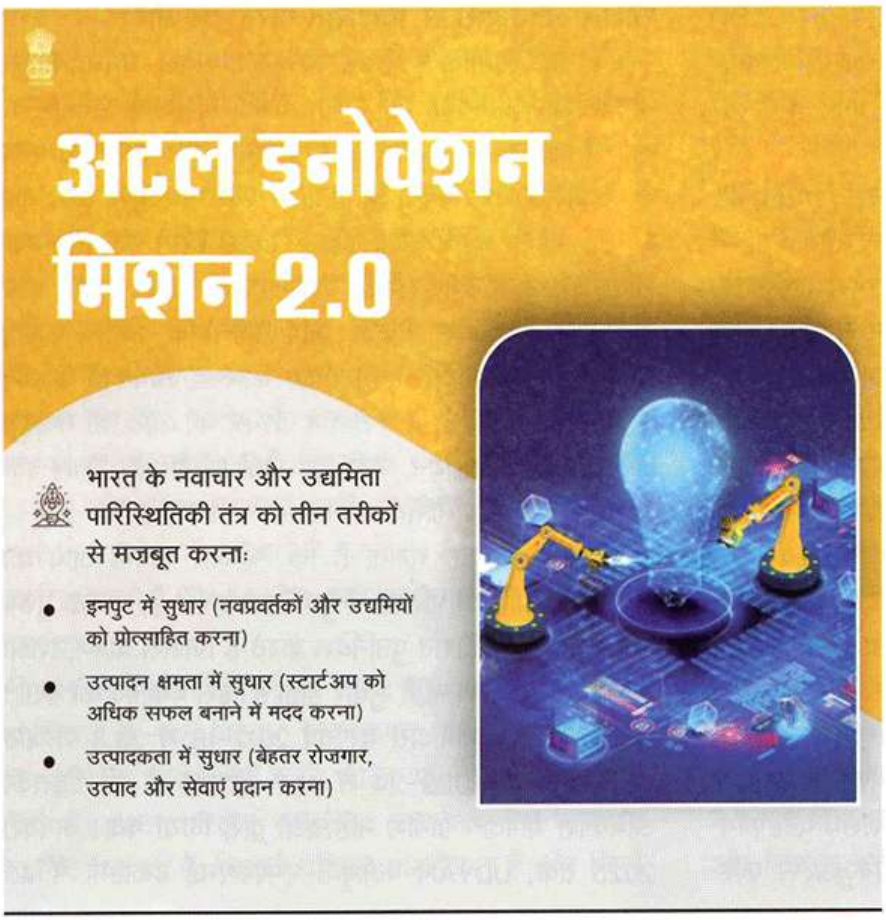

से सामने आ रहे हैं जिन तक वे मदद पहुँचाना चाहते हैं। ग्रामीण जिलों की महिलाएँ, आदिवासी क्षेत्रों के युवा नवप्रवर्तक, पहुँच-संबंधी समाधान डिज़ाइन करने वाले विकलांग व्यक्ति और समावेशी आजीविका मॉडल बनाने वाले ट्रांसजेंडर उद्यमी भारत के सोशल स्टार्टअप इकोसिस्टम को तेज़ी से आगे लेकर जा रहे हैं। जो क्षेत्र पहले 'संकीर्ण' माना जाता था, वह अब धीरे-धीरे एक मौन आर्थिक क्रांति बन चुका है और समाज के सभी वर्गों को भाग लेने के लिए प्रेरित करने वाला एक समावेशी क्षेत्र बन गया है।

समावेशी स्टार्टअप इकोसिस्टम का उदय

भारत के सोशल स्टार्टअप इकोसिस्टम की तेज़ वृद्धि और समावेशिता कोई संयोग नहीं है। यह सजग नीतिगत निर्णयों, लक्षित वित्तीय प्रोत्साहनों, मज़बूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे और भारत सरकार द्वारा निरंतर क्षमता निर्माण प्रयासों का परिणाम है। इन सभी तत्वों ने भारत को मिशन-उन्मुख उद्यमिता के लिए वैश्विक रूप से सबसे सहायक वातावरणों में से एक बना दिया है।

इस परिवर्तन के केंद्र में 'स्टार्टअप इंडिया' पहल है, जिसे 2016 में शुरू किया गया था। इसने स्टार्टअप मान्यता, कर लाभ और इन्क्यूबेशन समर्थन के लिए एक राष्ट्रीय ढाँचा तैयार किया। वर्ष 2025 तक, भारत में 1.9 लाख DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं, जिन्होंने सामूहिक रूप से 17 लाख से अधिक नौकरियाँ सृजित की हैं और 118 यूनिकॉर्न तैयार किए हैं। इस पारिस्थितिकी-तंत्र में सामाजिक मिशन पर काम करने वाले स्टार्टअप्स विशेषकर स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, जलवायु संरक्षण, शिक्षा और आजीविका जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे स्टार्टअप्स की संख्या लगातार बढ़ रही है।

एक और महत्वपूर्ण स्तंभ *अटल इनोवेशन मिशन* (AIM) है, जो कि *अटल इन्क्यूबेशन सेंटर*, ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में *अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र*, और प्रभाव-उन्मुख तकनीकों पर केंद्रित *अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज़* के माध्यम से सामाजिक नवाचार को बढ़ावा देता है। सीधे तौर पर स्टार्टअप कार्यक्रम न होते हुए भी, नीति आयोग का *आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम* स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और आजीविका जैसे क्षेत्रों में सामाजिक स्टार्टअप हस्तक्षेपों के लिए एक प्रभावी परीक्षण मैदान के रूप में उभरा है।

कई सरकार-समर्थित उपकरणों के माध्यम से वित्तीय पहुँच को मज़बूत किया गया है, जो प्रारंभिक चरण के उच्च प्रभाव वाले उद्यमों के लिए तैयार किए गए हैं। इनमें SIDBI द्वारा प्रबंधित *फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (FFS)* और *क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (CGSS)* शामिल हैं, जो बिना ज़मानत के ऋण की सुविधा प्रदान करती है। इसके पूरक *PMEGP, स्टैंडअप इंडिया, मुद्रा योजना, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म (WEP)* और *सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज़्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज़ (SMILE)* जैसी योजनाओं ने हज़ारों पहली पीढ़ी के उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं, SC/ST युवा, विकलांग व्यक्ति और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को औपचारिक क्रेडिट, प्रशिक्षण और मेंटरशिप तक पहुँचने में सक्षम बनाया है।

सपोर्ट फॉर मार्जिनालाइज़्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज (SMILE) जैसी योजनाओं ने हज़ारों प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों विशेषकर महिलाओं, SC/ST युवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर समुदाय को औपचारिक ऋण, प्रशिक्षण और मेंटरशिप तक पहुँच प्रदान की है।

इसी के साथ, डिजिटल समावेशन बड़े पैमाने पर परिवर्तन का एक सशक्त उत्प्रेरक बनकर उभरा है। *डिजिटल इंडिया, इंडिया स्टैक, UPI और JAM ट्रिनिटी* जैसे सुधारों के माध्यम से लाखों लोगों को भुगतान प्रणालियों, कल्याणकारी योजनाओं और आवश्यक सेवाओं से जोड़ा गया है। यह डिजिटल ढाँचा सामाजिक स्टार्टअप्स के लिए, विशेषकर अविकसित क्षेत्रों में, तेज़ी से विस्तार का उपजाऊ वातावरण तैयार कर रहा है।

जलवायु संरक्षण सरकारी पहलों ने उद्यम-आधारित समाधानों के लिए नए अवसर भी खोले हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन और मिशन LiFE जैसे कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के *ग्रीन क्लाइमेट फंड* जैसी पहलों के साथ मिलकर जल, ऊर्जा और कचरा प्रबंधन के क्षेत्रों में कार्यों को समर्थन देते हैं जिससे नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु अनुकूलन, सर्कुलर अर्थव्यवस्था मॉडलों और ग्रामीण हरित आजीविकाओं में नवाचार को बढ़ावा मिलता है।

सोशल स्टार्टअप्स से 'विकसित भारत' की ओर

शायद सामाजिक स्टार्टअप्स का सबसे परिवर्तनकारी योगदान उन समुदायों पर उनका प्रभाव है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से आर्थिक अवसरों से दूर रखा गया। इसी कारण वे भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गए हैं। महिला नेतृत्व वाला उद्यम विकास इसमें एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है। जब महिलाएँ माइक्रो उद्यमी, सौर इंजीनियर, ई-कॉमर्स विक्रेता, कृषि नवोन्मेषक, वित्तीय एजेंट, डिजिटल सहायक और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में सामने आती हैं, तो वे न केवल परिवार की आय को मज़बूत करती हैं बल्कि पलायन, पीढ़ी-दर-पीढ़ी गरीबी और शिक्षा तक पहुँच जैसी गहरी चुनौतियों का समाधान भी करती हैं।

साक्ष्यों से पता चलता है कि महिलाएँ अपनी आय का लगभग 90 प्रतिशत परिवार में पुनर्निवेश करती हैं, जबकि पुरुष केवल 30-40 प्रतिशत पुनर्निवेश करते हैं जिससे पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होता है। इस बदलाव को दर्शाते हुए महिला श्रम भागीदारी दर वर्ष 2017-18 में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7 प्रतिशत हो गई जिसका अधिकांश योगदान ग्रामीण महिलाओं द्वारा किया गया। जनवरी 2025 तक, UDYAM-पंजीकृत एमएसएमई इकाइयों में 40

प्रतिशत से अधिक, महिलाओं के स्वामित्व वाली हैं जिन्हें फ्रंटियर मार्केट्स, मन्न देशी, बेयरफुट कॉलेज और रंग जैसे स्टार्टअप्स का समर्थन प्राप्त है।

नवाचार-आधारित सशक्तीकरण ने दिव्यांग समुदायों के लिए अवसरों को भी व्यापक रूप से बदल दिया है। *Trestle Labs, BleeTech, Thinkerbell Labs* जैसी संस्थाएँ और *Atypical Advantage* जैसे उद्यम, जो सभी के रोज़गार-सक्षम होने पर केंद्रित हैं, यह दर्शाते हैं कि सहायक तकनीकों और समावेशी कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मानजनक और स्वतंत्र आजीविकाएँ सृजित की जा सकती हैं। ये प्रयास *सुगम्य भारत अभियान, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016* और *स्किल इंडिया* के समावेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसी राष्ट्रीय पहलों के अनुरूप हैं।

ट्रांसजेंडर उद्यमियों के लिए,जो लंबे समय तक मुख्यधारा की शिक्षा और रोज़गार से बाहर रखे गए,सामाजिक स्टार्टअप्स ने कौशल विकास, सौंदर्य एवं वेलनेस, डिजिटल साक्षरता, टिकाऊ हस्तशिल्प, सामुदायिक रसोई, वित्तीय समावेशन और लघु उद्यमों जैसे क्षेत्रों में नए रास्ते खोले हैं। *SMILE* और *राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड* जैसी योजनाओं के समर्थन से ये उद्यम सामाजिक परिवर्तन को टिकाऊ व्यावसायिक मॉडलों से जोड़ते हैं और समुदायों में क्षमता, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित करने के बेयरफुट कॉलेज के दर्शन को प्रतिध्वनित करते हैं।

भारत से विश्व तक

एक विविधता प्रधान देश में, उद्यमिता स्वयं अधिक विविध हो गई है। तकनीक, कौशल, वित्त और डिजिटल ज्ञान तक बढ़ी पहुँच ने व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में उद्यम शुरू करने का साहस दिया है। *हेल्थकेयर स्टार्टअप्स टेलीमेडिसिन*, AI-आधारित डायग्नोस्टिक्स और मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों के माध्यम से पहुँच के अंतर को पाटते हैं। कृषि स्टार्टअप्स नई खेती तकनीकों और बाज़ार से जोड़कर छोटे किसानों को मज़बूत बनाते हैं। *फिनटेक स्टार्टअप्स* डिजिटल पहचान की मदद से बिना बैंक खाते वाले लोगों तक ऋण पहुँचाते हैं, जबकि *एडटेक प्लेटफॉर्म्स* सरकारी स्कूलों के छात्रों को उनकी भाषा में पढ़ाई की सुविधाएँ देते हैं। वहीं, *सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप्स* कचरे से उपयोगी चीज़ें बनाते हैं, पर्यावरण के अनुकूल विकल्प विकसित करते हैं और स्थानीय-स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा समाधान तैयार करते हैं।

इन सभी क्षेत्रों को जोड़ने वाला सूत्र एक साझा उद्यमी मानसिकता है–जहाँ विस्तार, टिकाऊपन और सामाजिक लाभ एक-दूसरे का विरोध नहीं करते, बल्कि एक-दूसरे को मज़बूत बनाते हैं। आज भारतीय सामाजिक स्टार्टअप ऐसे समाधान विकसित कर रहे हैं, जिनकी वैश्विक प्रासंगिकता है और जिन्हें दुनिया भर के विकासशील देशों में दोहराया जा सकता है।

भारत में प्रभाव-आधारित निवेशकों, CSR साझेदारियों, परोपकारी वेंचर फंडों और मिश्रित वित्त मॉडलों का उभार भी देखा जा रहा है। SEBI द्वारा शुरू किया गया *सोशल स्टॉक एक्सचेंज* सामाजिक उद्यमों और गैर-लाभकारी संस्थाओं को पूंजी जुटाने के लिए एक पारदर्शी मंच प्रदान करता है, जो उच्च-प्रभाव वाले नवाचार के लिए नई वित्तीय संरचना निर्मित करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सतत विकास की नई राह

सामाजिक स्टार्टअप्स का उभार केवल व्यवसाय-आधारित सशक्तीकरण तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि उसने विकास की अवधारणा को ही पुनर्परिभाषित किया है। पारम्परिक मॉडल,जो केवल दान, राहत और कल्याण पर आधारित थे,गहन और परस्पर जुड़े सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में अपर्याप्त साबित हुए। इसके विपरीत, विस्तार, टिकाऊपन और बाज़ार अनुशासन पर आधारित उद्यम-चालित मॉडल अधिक लचीले और दीर्घकालिक प्रभाव वाले साबित हुए हैं। निजी उद्यमों और बाज़ार की भागीदारी से उन क्षेत्रों में पूँजी, ज़िम्मेदारी और नवाचार का प्रवेश हुआ है, जो पहले केवल सहायता पर निर्भर थे।

परिवर्तनकर्ताओं की सोच, सरकार का नीतिगत समर्थन और बाज़ारों से प्राप्त पूँजी–इन सबके साथ उद्यमिता सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली इंजन बन चुकी है। इसके परिणाम अब स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं: महिला इंजीनियरों द्वारा संचालित गाँव-स्तरीय सौर ग्रिड, युवाओं द्वारा बुज़ुर्ग आबादी के लिए निर्मित स्वास्थ्य उपकरण, सूखा-प्रभावित क्षेत्रों के लिए अनुकूलित जलवायु समाधान, और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्रांसजेंडर और दिव्यांग युवाओं को सम्मानजनक करियर बनाने में सक्षम बना रहे हैं और यह गति अभी केवल प्रारंभिक चरण में है।

फिर भी, सामाजिक स्टार्टअप्स को एक निर्णायक चुनौती का सामना करना होगा और वो है-'समय'। जटिल सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए धैर्य, निरंतर प्रयास और बहुस्तरीय वास्तविकताओं से जुड़ने की तत्परता आवश्यक है। त्वरित समाधान और अस्थायी उपाय अक्सर पर्याप्त नहीं होते। निरंतर सीखना, सहयोग और अनुकूलन अत्यंत आवश्यक हैं।

समावेशी विकास के लिए सभी हितधारकों–समुदाय, उद्यमी, कॉर्पोरेट, सरकार, शिक्षा जगत और निवेशक की सहभागिता आवश्यक है। सामाजिक उद्यमिता यह विचार स्थापित करती है कि विकास तभी टिकाऊ हो सकता है जब लोग निष्क्रिय लाभार्थी नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदार हों। जब समुदाय किसी सेवा के लिए भुगतान करते हैं और उसमें सहभागिता करते हैं, तो वे समान हितधारक बनते हैं जिससे समाधान सहभागी, क्रमिक और टिकाऊ बने रहते हैं। ❑